

सभी छोटे उद्यमियों को दें कॉमन फैसिलिटी सेंटर का लाभ : सचान

कारीगरों और बुनकरों को भी इन सेंटरों से जोड़ा जाएगा

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। ओडीओपी योजना के तहत स्थापित कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) का लाभ सीमित लोगों तक पहुंचने पर चिंता जताई गई। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री (एमएसएमई) राकेश सचान ने इसे कारीगरों, बुनकरों और सूक्ष्म उद्यमियों से जोड़ने के निर्देश दिए।

उन्हें आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण व विपणन से जोड़ा जाएगा। मंगलवार को मंत्री ने 16 सीएफसी परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री ने कई सीएफसी में सीमित लाभार्थियों पर चिंता व्यक्त की है और साफ किया है कि योजनाओं का लाभ सभी को मिलना चाहिए।

बैठक में बनकरों और कारीगरों ने बिजली, धागे



की लागत, बाजार प्रतिस्पर्धा व तकनीकी से जुड़े मुद्दे भी रखे। समीक्षा में बताया गया कि सरकार ने बुनकरों को राहत देने के लिए वर्षों तक फ्लैट रेट विद्युत योजना लागू रखी। इसके तहत 2006 से 31 मार्च 2023 तक लगभग 44 करोड़ रुपये का बिजली बिल सरकार ने वहन किया।

गाजियाबाद के इंजीनियरिंग एवं टूल रूम आधारित सीएफसी की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वहां 500 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और रक्षा क्षेत्र के लिए कंपोनेंट निर्माण पर काम हो रहा है। मुरादाबाद के फिजिकल वेपर डिपोजिशन (पीवीडी) प्लांट को पर्यावरण अनुकूल तकनीक का उदाहरण बताते हुए उसकी कार्यक्षमता को और मजबूत करने पर चर्चा हुई।

सीएफसी का कराएं प्रचार सचान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएफसी को जनहित से जोड़ते हुए व्यापक प्रचार अभियान चलाया जाए। साथ ही सभी सीएफसी में सिटीजन चार्टर भी लगाया जाएगा। बैठक में अंबेडकर नगर, मुरादाबाद, संभल, वाराणसी, खुर्जा, आगरा, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, अयोध्या और गाजियाबाद सहित विभिन्न जिलों की परियोजनाओं की समीक्षा की गई। अंबेडकर नगर बुनकर सीएफसी में लगभग 4 करोड़ रुपये की सहायता से स्थापित परियोजना में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया। बनारस के सिल्क उत्पाद सीएफसी में लगभग 9 करोड़ से कारीगरों तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा हुई।